पंचायती राज व्यवस्था में महिला जनप्रतिनिधि की राजनीतिक भूमिका एवं चुनौतियाँ : पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर प्रखण्ड के विशेष संदर्भ में

(2000–2023 तक)

बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद

के सामाजिक विज्ञान संकाय (राजनीति विज्ञान विभाग) में पीएच० डी० की उपाधि
हेतु शोध सार

शोधार्थी
लक्ष्मी कुमारी गुप्ता
पंजीकरण संख्या– (...)
द्वारा
राजनीति विज्ञान विभाग, बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद

पर्यवेक्षक
डॉ० धर्मेन्द्र कुमार सिंह (सहायक प्राध्यापक)
राजनीति विज्ञान विभाग, बीएस सिटी कॉलेज बोकारो,
धनबाद, झारखंड
बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद, झारखण्ड।

अक्टूबर, 2023

परिचय

पंचायती राज व्यवस्था जिसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, ग्रामीण विकास का प्रमुख आधार बना । जिससे गांव के व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र में भाग लेने का मौका मिला । इसका मुख्य उद्देश्य राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना ,उनमें जागरूकता लाना तथा उन्हें पूर्ण रूप से सशक्त बनाकर उनका विकास करना था । सच्चे लोकतंत्र की स्थापना तब मानी जाती है, जब केंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण की व्यवस्था को अपनाया जाए, तथा लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक अधिकार समान रूप से प्राप्त हो। पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का ही एक रूप है । जहां लोग सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी को बढ़ावा देते हैं, तथा निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहते हैं । ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है इसे लघु शासन के नाम से भी जाना जाता है। आजादी पूर्व से ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पंचायती राज व्यवस्था के जरिए पिछड़े समुदाय के हाथों में सत्ता सौंपने की कल्पना की थी तथा वह ग्रामीण पुनर्निर्माण में ग्राम पंचायत को मुख्य कड़ी मानते थे भारतीय ग्रामीण संस्थाओं में ग्राम पंचायत एक महत्वपूर्ण अंग रही है।

यदि हम ग्राम पंचायत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो यह हमारे देश के लिए कोई नई बात नहीं है प्राचीन काल से ही गांव में पंचायत का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। हमारे प्राचीन वेदों ,पुराणों ,धर्म ग्रंथो तथा स्मृतियों में ग्रामीण संस्कृति तथा ग्रामीण जीवन दिखाई पड़ता है। शुरू से ही गांव की पंचायतें ग्रामीण प्रशासन का अनिवार्य अंग रही है। शुरू से ही यदि हम देखें तो ग्राम पंचायत केवल प्रशासन का ही नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी आधार रही है। अलग–अलग युगों में कई प्रकार के परिवर्तन होते रहे कभी सामाजिक तौर पर कभी आर्थिक तौर पर परंतु ग्राम पंचायत का अस्तित्व प्रत्येक युग में किसी न किसी रूप में रहा है। हमारे देश में आरंभ से ही पंच को परमेश्वर कहकर पंचायत के महत्व को दर्शाया गया है।

पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए कई समितियां गठित की गई जो इस प्रकार है :–

(1) बलवंत राय मेहता समिति (1957) : इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की जिसमें जिला स्तर पर जिला परिषद ,ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, तथा गांव स्तर पर ग्राम पंचायत ।[1]

(2) अशोक मेहता समिति (1977) : इस समिति ने द्विस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया जिसमें जिला स्तर पर जिला परिषद एवं मंडल पंचायत शामिल था ।[2]

(3) जी०बी०के०राव समिति (1985): इस समिति ने गरीबी उन्मूलन तथा बुनियादी ढांचे के निर्माण की सिफारिश की।[3]

(4) लक्ष्मी सिंघवी समिति (1986): इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की ।[4]

(5) थुंगन समिति रिपोर्ट (1988): इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए कई सुझाव दिए।[5]

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में इस व्यवस्था की शुरुआत की गई थी । अंततः 73 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 , जिसे 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया तथा स्थानीय स्वशासन संस्था के रूप में इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया ।[6] महात्मा गांधी के स्वप्न को प्रत्यक्ष रूप में साकार करने का यह एक महत्वपूर्ण कदम था । इस संशोधन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया जहां जिला स्तर पर जिला परिषद , खंड स्तर पर पंचायत समिति तथा ग्राम स्तर पर ग्राम सभा होती है। अगर हम भारत की बात करें तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां महिलाओं ने अपना योगदान नहीं दिया हो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू , इंदिरा गांधी से लेकर वर्तमान में श्रीमती द्रोपदी मुर्मू तक महिलाएं गौरवशाली भूमिका निभा रही हैं । महिलाओं के गौरवशाली भूमिका निभाने के बावजूद भी यह खुलकर अपने बुद्धि और विवेक से ग्रामीण क्षेत्र के विकास में अपनी भूमिका का नेतृत्व नहीं कर पाती क्योंकि हमारा भारतीय समाज पुरुष प्रधान है और यहां अंतिम निर्णय पुरुष के द्वारा ही लिए जाते हैं। अतः महिलाओं की दोहरी चुनौतियां , निरक्षरता, राजनीति के प्रति उदासीनता , जातिगत बंधन , पारिवारिक समस्याएं , शिक्षा एवं प्रशिक्षण का अभाव , गरीबी पंचायत में महिलाओं की स्वतंत्र भूमिका निर्माण में बाधा बनी हुई है ।

झारखंड राज्य के चर्चित पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर प्रखंड जो विधानसभा का एक महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र है , यह जिला खनिज संपदा से संपन्न होने के बावजूद भी उतना विकसित नहीं हुआ जितना इसे अब तक होना चाहिए था। वह कहते हैं कि हर सफेद चेहरे के पीछे कुछ कालानुमा धब्बा होता है, ठीक उसी प्रकार खनिज संपदा से संपन्न इस जिले के अंतर्गत स्थिति कुछ ठीक नहीं है।

इस जिले के अंतर्गत 99 गांव तथा 15 प्रखंड आते है । जिसमें शोध का अध्ययन क्षेत्र मनोहरपुर प्रखंड होगा। जिसमें 15 पंचायत है। 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर ब्लॉक की कुल जनसंख्या 90,142 है , जिसमें पुरुष 45,441 है जबकि महिलाएं 44,671 है। यदि हम यहां के साक्षरता दर की बात करें तो शहरी क्षेत्र में औसत साक्षरता दर 76.1ः है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 55.6ः है।अर्थात मनोहरपुर प्रखंड में साक्षरता दर काफी कम है। जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या मे से 13.8ः लोग शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं जबकि 86.2 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। [7]

शहरी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति आधुनिकीकरण को अपनाने में लगे हुए हैं जबकि ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं से जूझ रहे हैं। मूलभूत आवश्यकताएं जैसे बिजली ,पानी, सड़क ,शिक्षा तथा स्वास्थ्य के अभाव में ग्रामीण लोग ग्रसित हैं । इसलिए यह आवश्यक हो जाता है की जिस प्रखंड की आधे से ज्यादा आबादी गांव में निवास करती हो ,वहां के ग्रामीण क्षेत्र का जायजा लिया जाए और वहां के बारे में शोध कर वहां की स्थिति ,समस्या तथा उपलब्धियों का पता लगाया जा सके और ग्राम पंचायती क्षेत्र की महिला जनप्रतिनिधि पर शोध कार्य कर उनकी वास्तविक स्थिति को सामने लाया जा सके। अतः इस प्रखंड पर शोध कार्य कर यहां की महिला जनप्रतिनिधियों की भूमिका का आकलन किया जाएगा ।

साहित्य की समीक्षा :

1. विजय (2011) : " महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता एक तुलनात्मक अध्ययन" : इसमें लेखिका का उद्देश्य यह है कि किस प्रकार राजनीतिक सहभागिता प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था का एक अनिवार्य तत्व होता है। वर्तमान लोकतांत्रिक युग तथा महिला मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता तथा महिला विकास के प्रति बढ़ती चेतना के फल स्वरुप जीवन के अन्य क्षेत्रों के साथ–साथ राजनीति में महिलाओं की सहभागिता आवश्यक एवं महत्वपूर्ण विषय बन गया है ।[8]

2. क्राफ्ट (1792) : " विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन" : इस किताब में वह राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं के स्थान व भूमिका और उनके स्वतंत्र होने की आवश्यकता के बारे में बात करती है। वह महिला के लिए शिक्षा का महत्व बताती है और तर्क देती है की अच्छी शिक्षित महिलाएं अच्छी पत्नियॉ और मां होगी और अंततः राष्ट्र के विकास में योगदान देगी।[9]

3. सीएसडीएस और कॉनराड एडिनॉयर स्टिंगटंग (2020) में एक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की जिसमें महिलाओं और उनकी राजनीतिक सक्रियता से संबंधित विभिन्न पहलू पर अध्ययन किया गया इसमें राजनीति में महिलाओं की भागीदारी में उनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति का विशेष प्रभाव को बताया गया है इस रिपोर्ट में राजनीति में पुरुषों का वर्चस्व तथा सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि की चर्चा की गई है।[10]

4. कोठारी (2010) "भारत में राजनीति कल और आज" : इस पुस्तक में दिखाया गया है कि हजारों साल पुराना एक पारंपरिक समाज किस तरह लोकतांत्रिक राजनीति के हाथों बदल रहा हैं।[11]

5. देवपुरा (2011) "ग्रामीण विकास का आधार आत्मनिर्भर पंचायते" : इस पुस्तक में इन्होंने गांव के विकास को चिन्हित करते हुए शहर तथा गांव के अंतर को दर्शाया है कि किस तरह शहरी क्षेत्र आधुनिकता की होड में लगे हैं वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र के लोग मूलभूत आवश्यकताओं से जूझ रहे हैं।[12]

6. बंसल (2004) "पंचायती राज में महिला भागीदारी" : इस पुस्तक में बताया गया है की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कितनी आवश्यक है ,लेकिन यह भी दर्शाया गया है की राजनीति में महिला उम्मीदवार निर्वाचित तो हो जाती हैं , परंतु वह अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं कर पाती क्योंकि उनमें जागरूकता की कमी है।[13]

7. तायल एवं कुमार (2011) "पंचायत राज व्यवस्था में महिलाओं की दशा एवं दिशा" : इस पुस्तक में ग्राम पंचायत और भारतीय महिलाओं को किस प्रकार आर्थिक रूप से स्वतंत्रता तथा कानूनी रूप से अधिकार दिए जा सकते हैं इसका प्रयास किया गया है।[14]

8. पंवर (2013) "पंचायती राज और ग्रामीण विकास" : इस पुस्तक में मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के बारे में बताया गया है, कि गांव के विकास का मूल स्रोत पंचायत है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत के द्वारा राजनीति के प्रति जागरूकता आ रही है।[15]

9. बसु (2017) भारत का संविधान एक परिचय" : दुर्गादास बसु ने इस पुस्तक में भारत के संविधान की उत्पत्ति और विकास को दर्शाया है,तथा व्यवस्थित रूप से संवैधानिक इतिहास, संवैधानिक संशोधन अधिनियम, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय है उन्हें शामिल किया है।

10. कश्यप (2017) हमारा संविधान भारत का संविधान और संवैधानिक विधि" : इस पुस्तक में सुभाष कश्यप ने संविधान का स्वरूप का परिचय देते हुए उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा संविधान निर्माण की प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से दर्शाया है।

उपरोक्त साहित्य समीक्षा से ज्ञात होता है कि इस विषय पर कई शोध हो चुके हैं , परंतु इस क्षेत्र पर अब तक कोई शोध नहीं हुआ है।

शोध समस्या का विवरण :

वास्तव में स्थानीय स्वशासन में आरक्षण के कारण महिलाओं की सहभागिता तो बड़ी है लेकिन उनकी स्थिति अति प्रशंसनीय नहीं है तथा महिलाओं के स्थान पर निर्णायक कर्ता के रूप में उनके पिता ,पति , भाई तथा पुत्र द्वारा भूमिका का निर्वाह किया जाता है । महिलाएं निर्वाचित तो होती है परंतु निर्णायक नहीं बन पाती यह बहुत बड़ी समस्या है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं खुलकर अपने बुद्धि तथा विवेक का उपयोग नहीं कर पाती इसलिए वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह आवश्यक हो जाता है , कि चुनाव के विभिन्न स्तर पर महिलाओं की भागीदारी का विश्लेषण कर इस बात का पता लगाया जा सके इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं।

महिलाओं को किन–किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है अशिक्षा,जागरूकता की कमी, तकनीकी शिक्षा, पारिवारिक बंधन जैसी समस्याओं का जांच किया जाएगा।

शोध का उद्देश्य :

1. ग्राम पंचायती क्षेत्र में महिला जनप्रतिनिधि की पंचायती राज व्यवस्था पर प्रभाव का विश्लेषण ।
2. त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में महिला जनप्रतिनिधि की सहभागिता पर 73वें संवैधानिक संशोधन के क्रियान्वयन का अध्ययन करना।
3. मनोहरपुर प्रखंड में महिला जनप्रतिनिधि की भूमिका का अध्ययन करना।
4. मनोहरपुर प्रखंड में महिला जनप्रतिनिधि की राजनीतिक भागीदारी का विश्लेषण करना।
5. मनोहरपुर प्रखंड में महिला जनप्रतिनिधि के प्रत्यक्ष राजनीति में आने वाली दोहरी चुनौतियों का अध्ययन करना।

शोध परिकल्पना :

1. ग्राम पंचायत की महिला जनप्रतिनिधि का पंचायती राज व्यवस्था पर सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों पभाव पड़ा है।

2. 73 वे संवैधानिक संशोधन में महिला आरक्षण के प्रभाव स्वरूप राजनीति में महिलाओं की सहभागिता बढ़ी है ।

3. मनोहरपुर प्रखंड में महिला जनप्रतिनिधि की भूमिका समाज में पितृ सत्तात्मकता के प्रभावी होने के कारण अपेक्षाकृत कम है।

4. मनोहरपुर प्रखंड में महिला जनप्रतिनिधि की राजनीतिक भागीदारी में शिक्षा तथा तकनीकी ज्ञान का अभाव है ।

5. पंचायती राज व्यवस्था में मनोहरपुर प्रखंड की महिला जनप्रतिनिधि को सामाजिक आर्थिक परिवेश के कारण दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

शोध प्रविधि :

प्रस्तुत शोध अध्ययन ऐतिहासिक, वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित होगा। इस शोध में सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग किया जाएगा।

शोध अभिकल्प :

1. महिला जनप्रतिनिधि के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य का विश्लेषण

2. महिला सशक्तिकरण व राजनीतिक सहभागिता के प्रमुख आयामो का विश्लेषण

3. मनोहरपुर प्रखंड में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता के आकलन के लिए प्रश्नावली के प्रस्तुतीकरण हेतु प्रतिदर्श का चयन

4. प्रश्नावली द्वारा तथ्यों का संकलन

5. तथ्यों का विश्लेषण

निष्कर्ष

तथ्यों के संग्रहण और विश्लेषण के लिए उपकरणों का प्रयोग :

शोध पद्धति के अंतर्गत तथ्यों का संकलन प्राथमिक तथा द्वितीय माध्यम से किया जाएगा।

शोध में प्राथमिक स्रोत जैसे – प्रश्नावली विधि , अनुसूची विधि, सरकारी व गैर सरकारी दस्तावेजों तथा साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया जाएगा ।

शोध में द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत इंटरनेट, पुस्तक, समाचार पत्र, जर्नल पत्र दृ पत्रिकाओं, लेखो व अन्य प्रकाशित व अप्रकाशित दस्तावेज, वेबसाइट, और रिपोर्ट्स का प्रयोग किया जाएगा।

शोध का महत्व

ग्राम पंचायती क्षेत्र में महिलाओं की वास्तविक स्थिति का पता चलेगा जिससे उनमें अधिक सुधार के लिए आगे बनाई जाने वाली योजनाओं के लिए अध्ययन पथ प्रदर्शक साबित होगा । आम महिलाओं के लिए भी यह अध्ययन राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बताकर उन्हें भी आगे लाने तथा प्रोत्साहित करने का काम करेगा। महिलाएं जब राजनीति में प्रवेश करती हैं तो उन्हें प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ता है इसके बावजूद महिला किस प्रकार राजनीति और घरेलू कार्यों के बीच समन्वय स्थापित करती हैं इस स्थिति का पता चलेगा और उनमें सुधार के लिए यह अध्ययन एक आधार बनेगा।

अध्ययन से महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति तथा राजनीतिक स्थिति का ज्ञान होगा तथा उसमें सुचारुता लाने में यह अध्ययन काम आएगा। इस शोध से न सिर्फ मनोहरपुर प्रखंड की महिलाएं बल्कि अन्य प्रखंड की महिलाएं भी राजनीति क्षेत्र के प्रति जागरूक होंगी तथा अपने भूमिका का निर्वाह जागरूकता के साथ करेंगी ।

शोध की सीमाएं और भविष्य के कार्य

अभी तक ग्राम पंचायत क्षेत्र में पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर प्रखंड के विशेष संदर्भ में महिलाओं की राजनीतिक भूमिका तथा चुनौतियों का गहन अध्ययन नहीं किया गया है इस शोध की सीमा होगी कि सूचना तथ्यों को छिपा कर दी जा सकती है क्योंकि महिलाओं की भी एक सीमित अभिव्यक्ति है। महिलाएं निर्वाचित तो होती है परंतु निर्णायक नहीं बन पाती। महिलाओं के स्थान पर निर्णयकर्ता के रूप में उनके पिता, पति, पुत्र द्वारा भूमिका का निर्वाह किया जाता हैं।

भविष्य में इस विषय पर शोध करने वाले शोधार्थियो के लिए यह शोध लाभदायक सिद्ध होगा। महिलाओं की भूमिका के आधार पर पुरुषों के साथ तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। इस शोध से ग्रामीण क्षेत्र के विकास में महिला जनप्रतिनिधि के प्रभाव को जानने में यह महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। इस क्षेत्र में शोध कार्य करने वाले शोधार्थियों को यहां की महिला जनप्रतिनिधि की दशा , दिशा , वास्तविक स्थिति तथा क्षेत्र में आने वाली समस्याओं तथा उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त हो सकती है तथा इसके आधार पर नए दृष्टिकोण से इस विषय पर शोध किया जा सकता है ।

संभावित अध्यायीकरण

प्रस्तावना

प्रथम अध्याय – सैद्धांतिक अवधारणा एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

द्वितीय अध्याय – 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का क्रियान्वयन एवं महिलाएं

तृतीय अध्याय – मनोहरपुर प्रखंड में महिला जनप्रतिनिधि की राजनीतिक भागीदारी

चतुर्थ अध्याय – मनोहरपुर प्रखंड में महिला जनप्रतिनिधि की भूमिका, नेतृत्व एवं चुनौतियां

पंचम अध्याय – मनोहरपुर प्रखंड के महिला जनप्रतिनिधियों के कारण पंचायती राज व्यवस्था पर प्रभाव

षष्ठम अध्याय – मनोहरपुर प्रखंड में सूचना संचार प्रौद्योगिकी का पंचायती राज व्यवस्था पर प्रभाव

निष्कर्ष

संदर्भ सूची

1. यादव, सिंह दयाशंकर(2022), पंचायती राज व्यवस्था में महिला प्रतिनिधि द्वारा ग्रामीण विकास, (एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण)

2. बसु, दुर्गा दास (2010), भारत का संविधान एक परिचय, 14वां संस्करण ,लेक्सिक नेक्सिक प्रकाशन

3. सेठ, अंजलि (2020), ग्रामीण क्षेत्र के विकास में महिला मुखिया की भूमिका व चुनौतियां, (बिहार राज्य के समस्तीपुर जिले के विशेष संदर्भ में)

4. कश्यप, सुभाष (1 जनवरी 2017), हमारा संविधान भारत का संविधान और संवैधानिक विधि , हिंदी संस्करण ,नेशनल बुक ट्रस्ट प्रकाशन

5. थुंगन समिति रिपोर्ट, (1988), भारत सरकार प्रतिवेदन , नई दिल्ली

6. तिवारी, गीता एवं हेमचंद्र (2019), पंचायती राज में महिलाओं की राजनीतिक, प्रशासनिक भूमिका : एक अवलोकन

7. भारतीय जनगणना रिपोर्ट , (2011)

8. विजय, संगीता (2011), महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता एक तुलनात्मक अध्ययन , नवजीवन प्रकाशन

9. क्राफ्ट, मेरी वॉल स्टोन (1792), विंडीकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन, प्रिंटेड फार जे जॉनसन

10. सीएसडीएस और कॉनराड एडिनॉयर स्टिंगटन (2020) रिपोर्ट

11. कोठारी,रजनी (1 जनवरी 2010),भारत में राजनीति कल और आज, वाणी प्रकाशन , तीसरा संस्करण

12. देवपुरा , प्रतापमाल (2006), ग्रामीण विकास का आधार आत्मनिर्भर पंचायतें, राधा कृष्ण प्रकाशन

13. बंसल ,वंदना (2004), पंचायती राज में महिला भागीदारी ,ज्ञान प्रकाशन

14. तायल, पीसी एवं कुमार रोहित (2011), पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की दशा एवं दिशा, नवराज प्रकाशन

15. पंवर , मीनाक्षी (2013),पंचायती राज और ग्रामीण विकास, हिंदी बुक स्टोर

ग्रंथ सूचीः

1. आहूजा, राम (1993) भारतीय सामाजिक व्यवस्था, नई दिल्ली, रावत प्रकाशन

2. कुमारी, सोनी (जनवरी 2014) पंचायती राज प्रणाली में सहभागिता, कुरुक्षेत्र वर्ष 1960 अंक

3. गुप्ता, डी. एन (2004) सुधार के लिए विकेंद्रीकरण की आवश्यकता , दिल्ली संकल्पना प्रकाशन

4. चोपड़ा,प्राण (2003) पंचायती राज पर बादल, द हिंदू ,सितंबर 13

5. चौहान, एस.पी.एस. कमलेश गुप्ता (2003), विकेंद्रीकरण के उभरते प्रतिमान,एसोसिएट पब्लिशिंग हाउस आगरा,पृष्ठ 19

6. चौहान, उपेंद्र (2001), उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत, प्रतियोगिता दर्पण,वर्ष 23(7) आगरा 40 1244–467 पेज 60–81

7. चौधरी, अंजना (2004), ग्रामीण समाज विज्ञान और वितरक , 116ध्ए दक्षिण अनारकली,नई दिल्ली

8. जोशी,बी.पी और जी .एस नरवानी (2002), भारत में पंचायती राज , रावत प्रकाशन,जयपुर

9. देसाई , बसंत (1980), लोगों की पंचायती राज सत्ता, मुंबई हिमालय , के प्रकाशन

10. दुबे,अवध नारायण (2002), नई पंचायती राज व्यवस्था, मिश्रा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन,वाराणसी 50– 76

11. पढ़ी, किशोर चंद्रा (1986), आधुनिक भारत में ग्रामीण विकास , नई दिल्ली, आर प्रशासन

12. महिपाल (2003), भारत में पंचायतों की आवश्यकता और स्त्रोत के बीच अन्तर , मित्तल प्रकाशन , नई दिल्ली

13. माहेश्वरी, एस.आर. (1985), भारत में ग्रामीण विकास , नई दिल्ली

14. मैथ्यू, जॉर्ज (2002), पंचायती राज के दुश्मन, द हिंदू, जनवरी

15. मिश्रा, एस.एन.मिश्रा श्वेता एवं चौताली पाल,(2000), विकेन्द्रीकरण मित्तल प्रकाशन, ए–110. मोहन गार्डन, नई दिल्ली